हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन का सरकारी क्षेत्र के अन्य एककों के साथ विलय किया जाना

1965. **श्री मूलचन्द मीणा:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन का सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य एककों के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन को कुल कितनी संचित हानि हुई है;

(ग) इस उपक्रम को अर्थक्षम बनाने हेतु क्या-क्या कदम उठाए हैं गये;

(घ) क्या सरकार के पास हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन को निजी पार्टियों को पट्टे पर देने का कोई अन्य प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड (एच०बी०ओ०सी०) का खाद्य तिलहनों/तेलों का कारबार करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के साथ विलय करने के प्रस्तावों पर विचार किया गया था लेकिन उसे कार्यरूप नहीं दिया जा सका क्योंकि संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उक्त विलय स्वीकार नहीं था।

(ख) कम्पनी को 1993-94 तक 18.46 करोड़ रुपए की संचित हानि हुई है।

(ग) हिन्दुस्तान वेजिटेबिल आयल्स कारपोरेशन को हुई हानि को नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम गए हैं। कम्पनी में अधिशेष कर्मचारियों में 670 कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के तहत दिए गए सेवानिवृत्ति के विकल्प के जरिए कमी की गई है। मितव्ययिता के अनेक उपाय अपनाए गए हैं यथा कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधाओं को रोकना/कम करना, निगमित कार्यालय को किराए के परिसर से अपने परिसर में स्थानान्तरित करना आदि। हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन ने कार्यों में आर्थिक-आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक आधुनिकीकरण का कार्यक्रम भी तैयार किया है।

(घ) व (ङ) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

Committee to decide Maximum Retail Price

1966. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:
SHRI O.P. KOHLI:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether the Committee set up to decide 'maximum retail price' (MRP) to be paid on a particular product, has since submitted its report;

(b) if so, what are the details of the recommendations made by the Committee and what action has been taken on each of the recommendations; and;

(c) if not, what are the reasons therefor and by when the Committee is expected to submit its report?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) Yes Sir.

(b) The Committee has recommended the maintenance of status quo in respect of "Maximum Retail Price".

(c) Does not arise.

Rise in Prices of Pulses in Delhi

1967. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether the prices of pulses have risen high in the recent past in Delhi;

(b) if so, the reasons thereof and the steps taken to contain the rise in prices thereof; and;

(c) the prices of pulses, pulse-wise and quality-wise, prevailing in the Super Bazar/Kendriya Bhandar/Open Market during the last 12 months, monthwise?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) and (c). A